पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2019 का आपराधिक पुनरीक्षण याचिका सं. 1008

थाना कांड संख्या-258 वर्ष-2004 थाना- नवगछिया जिला- भागलपुर से उत्पन्न

==========

मीरा देवी, पत्नी- शैलेंद्र कुमार साहू, निवासी- गाँव- साहू परबत्ता, थाना-परबत्ता, जिला-भागलपुर।

..... याचिकाकर्ता/गण

बनाम

1. बिहार राज्य

2. राघवेंद्र कुमार साहू, पुत्र- जितेंद्र कुमार साहू, निवासी- गाँव-साहू परबत्ता, थाना-परबत्ता, जिला-भागलपुर।

....प्रत्यर्थी/गण

==========

उपस्थिति:

याचिकाकर्ता/ओं के लिए	:	श्री ब्रजेश कुमार सिंह, अधिवक्ता
राज्य के लिए	:	श्री अरुण कुमार पांडे, एपीपी
विपक्षी सं. 2 के लिए	:	श्री धनंजय कुमार गुप्ता, अधिवक्ता

==========

अधिनियम/धाराएँ/नियम:

- *भारतीय दंड संहिता की धाराएँ 448 और 323*

संदर्भित मामले:

- *मल्लिकार्जुन कोडागली बनाम कर्नाटक राज्य, (2019) 2 एससीसी 752*
- *जोसेफ स्टीफन बनाम संथानसामी, (2022) 13 एससीसी 115*
- *रेणु मिश्रा बनाम झारखंड राज्य और अन्य (झारखंड उच्च न्यायालय आपराधिक संशोधन संख्या 520/2019 का निर्णय 18.04.2024 को हुआ)*

पुनरीक्षण याचिका – उस आदेश के विरुद्ध दायर की गई जिसमें अपीलीय न्यायालय ने दोषसिद्धि एवं दंडादेश को निरस्त कर दिया।

प्रारंभिक आपत्ति यह उठाई गई कि वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण याचिका न्यायालय में पोषणीय नहीं है।

निर्णय – याचिकाकर्ता की इस दलील में कोई बल नहीं है कि अपीलीय न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध कोई आपराधिक अपील नहीं की जा सकती। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि आपराधिक अपील का उपाय विधिक प्रावधानों से उत्पन्न होता है, और जब तक दंड प्रक्रिया संहिता (दं. प्र. सं.) या समय-समय पर लागू किसी अन्य विधि में इसका प्रावधान न हो, तब तक कोई अपील विचारणीय नहीं होती। (पैरा 21)

सामान्यतः आपराधिक अपीलों में पारित निर्णयों एवं आदेशों की अंतिमता होती है। किंतु धारा 393 दं. प्र. सं. में कुछ अपवादों का प्रावधान किया गया है, जहाँ इस धारा को धारा 377, 378 एवं 384 दं. प्र. सं. के अधीन माना गया है, जिनके अंतर्गत हाई कोर्ट में अपीलीय निर्णयों के विरुद्ध भी अपील की अनुमति है। यहाँ तक कि धारा 372 दं. प्र. सं. के प्रावधान में भी ऐसा कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है कि ऐसी अपील केवल ट्रायल कोर्ट के निर्णयों के विरुद्ध ही दायर की जा सकती है। (पैरा 21)

दं. प्र. सं.की धारा 401(4) में प्रावधान है कि जहाँ आपराधिक अपील की संभावना है और अपील दायर नहीं की गई है, वहाँ वह पक्ष जो अपील कर सकता था, उसकी ओर से पुनरीक्षण याचिका विचारणीय नहीं है। हालांकि, धारा 401(5) न्यायालय को यह अधिकार देती है कि वह ऐसी पुनरीक्षण याचिका को आपराधिक अपील में परिवर्तित कर उसके अनुसार विचार करे। (पैरा 22)

याचिकाकर्ता को दं. प्र. सं. की धारा 372 के प्रावधान के अंतर्गत इस न्यायालय में बिना किसी पूर्व अनुमति के आपराधिक अपील दायर करने का वैधानिक उपाय उपलब्ध था। तथापि, याचिकाकर्ता ने वर्तमान पुनरीक्षण याचिका दाखिल की। परंतु चूँकि याचिकाकर्ता के पास वैकल्पिक उपाय के रूप में आपराधिक अपील दायर करने का अधिकार उपलब्ध था, अतः वर्तमान पुनरीक्षण याचिका दं. प्र. सं. की धारा 401(4) के प्रावधान से बाधित होती है। फिर भी, धारा 401(5) के अंतर्गत न्यायालय को यह

अधिकार है कि वह इस पुनरीक्षण याचिका को आपराधिक अपील में परिवर्तित कर दे और गुण-दोष के आधार पर उसका निर्णय करे। (पैरा 27)

अतः यह आपराधिक पुनरीक्षण याचिका आपराधिक अपील में परिवर्तित की जाती है। (पैरा 28)

==========

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

गणपूर्ति : माननीय न्यायमूर्ति श्री जितेंद्र कुमार

सीएवी निर्णय

तारीखः 04-04-2025

वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण याचिका याचिकाकर्ता/मीरा देवी (सुचक) द्वारा विद्वान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-III, नवगछिया द्वारा आपराधिक अपील संख्या 75/2018 में पारित दिनांक 09.07.2019 के आक्षेपित निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके तहत ओ.पी. संख्या 2/राघवेंद्र कुमार साहू द्वारा दायर आपराधिक अपील को स्वीकार किया गया है, जिसमें श्री राहुल कुमार, विद्वान ए.सी.जे.एम-III, नवगछिया द्वारा जी.आर. केस संख्या 559/2004 में पारित दोषसिद्धि के निर्णय और दिनांक 31.07.2018 के सजा के आदेश को खारिज कर दिया गया है, जो परबत्ता थाना कांड संख्या 258/2004 से संबंधित है, जिसके तहत राघवेंद्र कुमार साहू को भारतीय दंड संहिता की धारा 448 और 323 के तहत दोषी पाया गया था और तदनुसार सजा सुनाई गई थी।

<u>तथ्यात्मक पृष्ठभूमि</u>

2. मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि यह है कि पीड़ितों में से एक मीरा देवी, जो इस मामले में याचिकाकर्ता हैं, के फर्दबयान के आधार पर परबत्ता थाना कांड संख्या 258/2004 दिनांक 14.08.2004 को राघवेंद्र कुमार साहू (इस मामले में विपक्षी संख्या 2) के विरुद्ध दर्ज किया गया था।

3. जाँच के बाद, आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया, संज्ञान लिया गया और भारतीय दंड संहिता की धारा 448,323,341 और 504 के तहत आरोप तय किए गए और उसके बाद, मुकदमा शुरू हुआ और मुकदमे के दौरान, एकमात्र आरोपी राघवेंद्र कुमार साहू को भारतीय दंड संहिता की धारा 448 और 323 के तहत विद्वान मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा दोषी पाया गया, लेकिन उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 341 और 504 के तहत बनाए गए आरोपों से बरी कर दिया गया।

4. तत्पश्चात, राघवेन्द्र कुमार साहू ने दिनांक 31.07.2018 के दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के निर्णय के विरूद्ध आपराधिक अपील संख्या 75/2018 प्रस्तुत की। उसी अपील को स्वीकार करते हुए उसे सभी आरोपों से बरी कर दिया गया, अतः पीड़ित/सूचनाकर्ता मीरा देवी ने व्यथित होकर निम्न विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि के निर्णय के विरुद्ध वर्तमान पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की है।

<u>पक्षों की दलीलें</u>

5. हालांकि, पुनरीक्षण याचिका की सुनवाई के दौरान, राज्य के लिए विद्वान एपीपी और विपक्षी नंबर 2 के लिए विद्वान वकील द्वारा प्रारंभिक आपत्ति जताई गई है कि वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण याचिका विचारणीय नहीं है।

6. वे प्रस्तुत करते हैं कि धारा 378 दं.प्र.सं के साथ पठित धारा 372 के प्रावधान को देखते हुए, याचिकाकर्ता को इस न्यायालय की अनुमति प्राप्त करने के बाद

आपराधिक अपील दायर करनी चाहिए थी। वे आगे प्रस्तुत करते हैं कि वर्तमान आपराधिक संशोधन दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 401 (4) द्वारा प्रभावित है।

7. इसके विपरीत, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि आपराधिक अपील संख्या 75/2018 में निचली अपीलीय अदालत द्वारा ओ.पी. संख्या 2 को बरी किए जाने के मद्देनजर, याचिकाकर्ता/सूचनाकर्ता/पीड़ित ने सही ढंग से वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण दायर किया है, क्योंकि निचली अपीलीय अदालत द्वारा पहले ही विवादित निर्णय पारित किया जा चुका है और अपीलीय निर्णय के खिलाफ कोई और अपील नहीं की जा सकती। ऐसी परिस्थितियों में, पीड़ित/याचिकाकर्ता के पास एकमात्र उपाय यह बचा था कि वह विवादित निर्णय के खिलाफ आपराधिक पुनरीक्षण दायर करे।

विचारणीय

8. मैंने दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर विचार किया और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री का अवलोकन किया।

सवाल यह है कि

9. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, सवाल यह है कि बरी करने के अपीलीय फैसले के खिलाफ पीड़ित/याचिकाकर्ता के लिए कानूनी उपाय क्या है-क्या याचिकाकर्ता ने सही ढंग से आपराधिक संशोधन दायर किया है या उसे इस अदालत की अनुमति के साथ या उसके बिना आपराधिक अपील दायर करनी चाहिए थी।

कानूनी प्रावधान

10. बरी होने के मामले में आपराधिक अपील धारा 378 दं.प्र.सं के तहत प्रदान की जाती है, जो इस प्रकार हैः

"दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 378 दोषमुक्त किए जाने के मामले में अपील करती है।-

[(1) उप-धारा (2) में अन्यथा उपबंधित को छोड़कर, और उप-धारा (3) और (5) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए,

(ए) जिला मजिस्ट्रेट, किसी भी मामले में, लोक अभियोजक को किसी संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध के संबंध में मजिस्ट्रेट द्वारा पारित बरी किए जाने के आदेश से सत्र न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकता है;

(बी) राज्य सरकार, किसी भी मामले में, लोक अभियोजक को उच्च न्यायालय के अलावा किसी अन्य न्यायालय द्वारा पारित बरी किए जाने के मूल या अपीलीय आदेश से उच्च न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकती है। [खंड (क) के तहत आदेश नहीं होने के कारण] या सत्र न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण में पारित बरी करने का आदेश।]

(2) यदि बरी करने का ऐसा आदेश किसी ऐसे मामले में पारित किया जाता है जिसमें दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम, 1946 (1946 का 25) के तहत गठित दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान द्वारा या इस संहिता के अलावा किसी अन्य केंद्रीय अधिनियम के तहत किसी अपराध की जांच करने के लिए सशक्त किसी अन्य एजेंसी द्वारा अपराध की जांच की गई है, तो केंद्र सरकार, उप-धारा (3) के प्रावधानों के अधीन, लोक अभियोजक को एक अपील प्रस्तुत करने का भी निर्देश दे सकती है-

(क) सत्र न्यायालय को, किसी संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध के संबंध में मजिस्ट्रेट द्वारा पारित बरी करने के आदेश से;

(ख) उच्च न्यायालय को उच्च न्यायालय के अलावा किसी अन्य न्यायालय द्वारा पारित बरी किए जाने के मूल या अपीलीय आदेश से [जो खंड (क) के तहत आदेश या सत्र न्यायालय द्वारा संशोधन में पारित बरी किए जाने का आदेश नहीं है।

(3) उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के तहत किसी भी अपील पर उच्च न्यायालय की अनुमति के अलावा विचार नहीं किया जाएगा।

(4) यदि शिकायत पर स्थापित किसी भी मामले में बरी करने का ऐसा आदेश पारित किया जाता है और उच्च न्यायालय, इस ओर से शिकायतकर्ता द्वारा किए गए आवेदन पर, बरी करने के आदेश से अपील करने के लिए विशेष अनुमति देता है, तो शिकायतकर्ता उच्च न्यायालय में ऐसी अपील प्रस्तुत कर सकता है।

(5) उप-धारा (4) के तहत बरी करने के आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए विशेष अनुमति देने के लिए किसी भी आवेदन पर उच्च न्यायालय द्वारा छह महीने की समाप्ति के बाद विचार नहीं किया जाएगा, जहां शिकायतकर्ता एक लोक सेवक है, और प्रत्येक अन्य मामले में साठ दिन, बरी करने के उस आदेश की तारीख से गणना की जाती है।

(6) यदि, किसी भी मामले में, दोषमुक्ति के आदेश से अपील करने के लिए विशेष अनुमति देने के लिए उप-धारा (4) के तहत आवेदन अस्वीकार कर दिया जाता है, तो दोषमुक्ति के उस आदेश से कोई अपील उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के तहत नहीं होगी।

(जोर दिया गया)

11. उप-धारा (1), (2) और (3) पुलिस मामले में बरी होने के मामले में अपील से संबंधित हैं, जबकि उप-धारा (4) शिकायत पर स्थापित किसी भी मामले में बरी होने के खिलाफ अपील का प्रावधान करती है।उप-धारा (5) में धारा 378 के तहत ऐसी अपील दायर करने के लिए सीमा अवधि का प्रावधान है, जबकि उप-धारा (6) में प्रावधान है कि यदि उप-धारा (4) के तहत अपील करने के लिए विशेष अनुमति देने से इनकार कर दिया जाता है, तो कोई अपील दायर नहीं की जा सकती है।धारा 378 (1) और 378 (2) के तहत, उच्च न्यायालय की अनुमति के बगैर उच्च न्यायालय में कोई अपील दायर नहीं की जा सकती है।पुनः, धारा 378(4) दं.प्र.सं. के तहत अपील केवल शिकायतकर्ता को विशेष अनुमति प्रदान करने के बाद ही उच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है।

12. धारा 372 दं.प्र.सं में प्रावधान है कि इस न्यायालय या उस समय लागू किसी अन्य कानून द्वारा प्रदान किए गए प्रावधान को छोड़कर, आपराधिक न्यायालय के किसी भी निर्णय या आदेश से कोई अपील नहीं होती है।इसका मतलब है कि कोई भी आपराधिक अपील दायर नहीं कर सकता है, सिवाय इसके कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता या उस समय लागू किसी अन्य कानून में प्रावधान है।यह भी इंगित करना उचित है कि वर्ष 2009 में धारा 372 में प्रावधान को जोड़ने से पहले, पीड़ित को धारा 378 (4) के तहत किसी भी आपराधिक अपील को दायर करने का कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं था, जो शिकायतकर्ता को उच्च न्यायालय द्वारा शिकायतकर्ता को विशेष अनुमति देने के अधीन, शिकायत पर स्थापित किसी भी मामले में बरी होने के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर करने का अधिकार प्रदान करता है।

13. हालाँकि, धारा 372 दं.प्र.सं के प्रावधान में अपराध की पीड़ित को विशेष अधिकार प्रदान किया गया है कि वह अभियुक्त को बरी करने या कम अपराध के लिए

दोषी ठहराने या अपर्याप्त मुआवजा देने के न्यायालय द्वारा पारित किसी भी आदेश के खिलाफ अपील करे और ऐसी अपील उस न्यायालय में होती है, जिसमें आमतौर पर ऐसे न्यायालय के दोषसिद्धि के आदेश के खिलाफ अपील की जाती है।

14. धारा 372 दं.प्र.सं के प्रावधान के तहत पीड़ित द्वारा अपील दायर करने की प्रक्रिया के बारे में राय में मतभेद था। एक दृष्टिकोण के अनुसार, पीड़ित का धारा 372 दं.प्र.सं के प्रावधान के तहत उच्च न्यायालय में अपील दायर करने का अधिकार निरपेक्ष नहीं है।पीड़ित को धारा 378 दं.प्र.सं की उप-धारा (3) और (4) के तहत उच्च न्यायालय द्वारा छुट्टी या विशेष अनुमति देने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, एक अन्य दृष्टिकोण के अनुसार, पीड़ित का धारा 372 दं.प्र.सं के प्रावधान के तहत भी उच्च न्यायालय में अपील दायर करने का अधिकार निरपेक्ष नहीं है और पीड़ित को धारा 378 दं.प्र.सं की उप-धारा (3) और (4) के तहत उच्च न्यायालय से अनुमति या विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है ताकि उसके समक्ष अपील दायर की जा सके।

15. हालाँकि, **मल्लिकार्जुन कोडागली बनाम कर्नाटक राज्य, (2019) 2 एससीसी 752** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आधिकारिक निर्णय द्वारा विवाद सुलझ गया है। तीन न्यायाधीशों की पीठ के बहुमत के अनुसार, धारा 372 दं.प्र.सं के प्रावधान के तहत अपील दायर करने का पीड़ित का अधिकार पूर्ण है और पीड़ित को उच्च न्यायालय में अपील दायर करने के लिए किसी अनुमति या विशेष अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

16. मल्लिकार्जुन कोडागली मामले (उपरोक्त) में, हमले की पीड़िता ने पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके कारण आरोपी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। सत्र न्यायालय द्वारा किए गए अनुवर्ती परीक्षण में, आरोपी को विचारण न्यायालय द्वारा बरी कर दिया गया था। इसके बाद, पीड़िता ने बरी किए

जाने के खिलाफ धारा 372 दं.प्र.सं के प्रावधान के तहत 06.02.2009 को उच्च न्यायालय में आपराधिक अपील दायर की। लेकिन अपील को बनाए रखने योग्य नहीं मानते हुए खारिज कर दिया गया, जिसमें कहा गया कि धारा 372 का प्रावधान 31.12.2009 से प्रभावी हुआ और घटना उस तारीख से काफी पहले हुई थी। इसके बाद, पीड़िता ने धारा 378(4) दं.प्र.सं के तहत उच्च न्यायालय में एक और आपराधिक अपील दायर की। हालांकि, इस अपील को भी बनाए रखने योग्य नहीं माना गया, जिसमें कहा गया कि मामला मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत के आधार पर शुरू नहीं किया गया था। इसलिए, उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ, पीड़िता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की।

17. **मल्लिकार्जुन कोडगली मामले** (उपरोक्त) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 372 और धारा 378 पर बहुत विस्तार से चर्चा की और पीड़ित की अपील को अनुमति दी गई, उच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार करते हुए और मामले को उच्च न्यायालय में सुनवाई के लिए भेज दिया गया।पीड़िता द्वारा उच्च न्यायालय में दायर की गई अपील दं.प्र.सं की धारा 372 के प्रावधान के तहत विचारणीय थी। चर्चा के दौरान, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

> "73. हमारी राय में, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 372 के प्रावधान को भी एक ऐसा अर्थ दिया जाना चाहिए जो यथार्थवादी, उदार, प्रगतिशील और अपराध के पीड़ित के लिए फायदेमंद हो। इसका एक ऐतिहासिक कारण है, जिसकी शुरुआत अपराध और शक्ति के दुरुपयोग के पीड़ितों के लिए न्याय के बुनियादी सिद्धांतों की घोषणा से होती है, जिसे संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा 29-11-1985 पर 96 वें पूर्ण सत्र में अपनाया गया था।
>
> .....

74. घोषणा को व्यवहार में लाते हुए, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि अपराध का शिकार व्यक्ति विभिन्न अधिकारों का हकदार है। राष्ट्रीय विधान में प्रदान की गई औपचारिक प्रक्रियाओं के माध्यम से न्याय और निवारण के तंत्र तक पहुंच में, किसी मामले में बरी होने के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने का अधिकार शामिल होना चाहिए, जैसे कि वर्तमान में हम जिस मामले से संबंधित हैं। इस संदर्भ में, इसमें कोई संदेह नहीं है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 372 के प्रावधान को अपराध के पीड़ित को लाभ पहुँचाने के लिए आजीवन कारावास दिया जाना चाहिए।

75. इन परिस्थितियों में, कानून की सरल भाषा के आधार पर और कई उच्च न्यायालयों द्वारा व्याख्या किए गए और संयुक्त राष्ट्र की महासभा के प्रस्ताव के अलावा, हमारे लिए यह बिल्कुल स्पष्ट है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 (डब्ल्यू) में परिभाषित एक पीड़ित अदालत के समक्ष अपील दायर करने का हकदार होगा, जिसमें आम तौर पर दोषसिद्धि के आदेश के खिलाफ अपील की जाती है। इससे यह पता चलता है कि उच्च न्यायालय के समक्ष कोडगली द्वारा दायर अपील विचारणीय थी और इस पर अपने गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाना चाहिए था।

76. जहाँ तक विशेष अवकाश देने के सवाल का सवाल है, एक बार फिर, हमें बार में की गई दलीलों से अभिभूत होने की आवश्यकता नहीं है। धारा 372 दं.प्र.सं के प्रावधान की भाषा काफी स्पष्ट है, विशेष रूप से जब यह धारा 378 (4) सी. आर. पी. सी. की भाषा से विपरीत है। इस प्रावधान का मूल पाठ काफी स्पष्ट है और यह शिकायत पर स्थापित मामले में बरी किए जाने के आदेश तक सीमित है।"शिकायत" शब्द को

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 (डी) में परिभाषित किया गया है और यह मजिस्ट्रेट को मौखिक रूप से या लिखित रूप में दिए गए किसी भी आरोप को संदर्भित करता है। इसका प्राथमिकी दर्ज करने या दर्ज करने से कोई लेना-देना नहीं है, और इसलिए जहां तक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 372 के प्रावधान का संबंध है, पीड़ित के शिकायतकर्ता होने के प्रभाव पर विचार करना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है।

अंतिम आदेश

77. उपर्युक्त कारणों से, अपीलों को स्वीकार किया जाता है और मल्लिकार्जुन कोडगली बनाम कर्नाटक राज्य, उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश को रद्द किया जाता है और मामलों को उच्च न्यायालय को वापस भेजा जाता है ताकि वह जिला और सत्र न्यायाधीश, बागलकोट (कर्नाटक) द्वारा एससी संख्या 49/2010 में पारित दिनांक 28-10-2013 के निर्णय और बरी करने के आदेश के खिलाफ कोडगली द्वारा दायर अपील पर सुनवाई और निर्णय कर सके।

(जोर दिया गया)

18. हालांकि, **मल्लिकार्जुन कोडगली मामले** (उपरोक्त) में अल्पमत के अनुसार, धारा 372 दं.प्र.सं के प्रावधान के तहत अपील दायर करने के पीड़ित के अधिकार को अलग से नहीं पढ़ा जा सकता है। इसे दं.प्र.सं की धारा 378(3) और धारा 378(4) के साथ पढ़ा जाना चाहिए, जो उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर करने से पहले उच्च न्यायालय की अनुमति या विशेष अनुमति देने का प्रावधान करता है। पीड़ित के अधिकार को आरोपी के अधिकार के साथ संतुलित किया जाना चाहिए। जब व्यक्ति को बरी कर दिया जाता है, तो आरोपी की निर्दोषता की धारणा मजबूत हो जाती है। इसलिए, उच्च न्यायालय को मामले पर गौर करना चाहिए और पहले यह तय करना

चाहिए कि अपील दायर करने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त कारण हैं या नहीं। ऐसा कोई कारण नहीं है कि पीड़ित द्वारा दायर अपील में ऐसी जांच न की जाए। पीड़ित को राज्य या शिकायत से उपरोक्त नहीं रखा जा सकता है।

19. जोसेफ स्टीफन बनाम संथानसामी, (2022) 13 एससीसी 115 इस मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय का एक और ऐतिहासिक फैसला है, जो **मल्लिकार्जुन कोडगली मामले** (उपरोक्त) पर भरोसा करते हुए सर्वोच्च न्यायालय की माननीय खंडपीठ द्वारा सुनाया गया। इस मामले में, आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 324 और 326 के तहत दोषी ठहराया गया था, लेकिन उन्हें धारा 307 और 506 आईपीसी के तहत लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया गया था। दोषियों ने सत्र न्यायालय के समक्ष दोषसिद्धि के फैसले के खिलाफ आपराधिक अपील की और पीड़िता ने धारा 307 और 506 आईपीसी के तहत आरोपों से बरी करने के फैसले के खिलाफ सत्र न्यायालय के समक्ष अपील की। एक सामान्य निर्णय द्वारा, अभियुक्तों की अपील को अनुमति दी गई, जबकि पीड़िता की अपील को खारिज कर दिया गया, जिसमें आरोपी को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। अतः प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति के निर्णय से व्यथित होकर, पीड़ित ने धारा 397 सहपठित धारा 401 दं.प्र.सं के अंतर्गत उच्च न्यायालय के समक्ष आपराधिक पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की। उच्च न्यायालय ने धारा 401 दं.प्र.सं के अंतर्गत पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति के निर्णय को निरस्त कर दिया तथा ट्रायल न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि के निर्णय तथा सजा के आदेश को बहाल कर दिया। विचार-विमर्श के दौरान, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न प्रकार से टिप्पणी की:

"8. हमने संबंधित पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना है। संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के पश्चात, इस न्यायालय के विचारार्थ निम्नलिखित प्रश्न उठते हैं:

8.1. (i) क्या उच्च न्यायालय द्वारा धारा 401 दं.प्र.सं के अंतर्गत पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए दोषमुक्ति के आदेश को निरस्त करना तथा दोषमुक्ति के निष्कर्ष को दोषसिद्धि में परिवर्तित करके अभियुक्त को दोषी ठहराना न्यायोचित है?

8.2. (ii) ऐसे मामले में जहां पीड़ित को दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध अपील करने का अधिकार है, जैसा कि धारा 372 दं.प्र.सं के अंतर्गत अब प्रदान किया गया है तथा पीड़ित ने ऐसा कोई उपाय नहीं अपनाया है तथा अपील नहीं की है, क्या अपील करने के स्थान पर पक्षकार/पीड़ित के कहने पर पुनरीक्षण आवेदन पर विचार किया जाना आवश्यक है?

8.3. (iii) धारा 401दं.प्र.सं की उपधारा (5) के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए पुनरीक्षण आवेदन पर विचार करते हुए अपील की याचिका के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए तथा उसके अनुसार निपटा जाना चाहिए, क्या उच्च न्यायालय को न्यायिक आदेश पारित करने की आवश्यकता है? .....

13. अब जहां तक मुद्दा (ii) का संबंध है, अर्थात्, ऐसे मामले में जहां कोई अपील नहीं की गई है, यद्यपि अपील संहिता के अंतर्गत आती है, क्या अपील करने वाले पक्षकार के अनुरोध पर पुनरीक्षण आवेदन पर अभी भी विचार किया जाना है, इसका उत्तर धारा 401 दं.प्र.सं की उपधारा (4) में ही निहित है। धारा 401 दं.प्र.सं की उपधारा (4) इस प्रकार है:

"401. (4) जहां इस संहिता के तहत अपील की जाती है और कोई अपील नहीं की जाती है, उस पक्षकार के कहने पर पुनरीक्षण के माध्यम से कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी जो अपील कर सकता था।

13.1. यह विवादित नहीं हो सकता है कि अब धारा 372 दं.प्र.सं में 2009 के बाद संशोधन और धारा 372 दं.प्र.सं में प्रावधान डालने के

बाद, पीड़ित को बरी के आदेश के खिलाफ अपील करने का वैधानिक अधिकार है। इसलिए, ऐसे मामले में जहां कोई अपील पेश नहीं की जाती है और पीड़ित को अपील दायर करने के लिए भेजा जाना है, बरी के आदेश के खिलाफ पीड़ित के कहने पर कोई पुनरीक्षण नहीं माना जाएगा। यहां तक कि यह पीड़ित के स्वयं के हित में होगा क्योंकि पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय, दायरा बहुत सीमित होगा, हालांकि, पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय अपीलीय क्षेत्राधिकार के तहत, अपीलीय न्यायालय के पास पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार की तुलना में व्यापक क्षेत्राधिकार होगा। इसी तरह, ऐसे मामले में जहां शिकायत पर शुरू किए गए किसी मामले में दोषमुक्ति का आदेश पारित किया जाता है, शिकायतकर्ता (पीड़ित के अलावा) धारा 378 दं.प्र.सं की उपधारा (4) के तहत दोषमुक्ति के आदेश के खिलाफ अपील कर सकता है, बशर्ते कि उच्च न्यायालय द्वारा अपील करने की विशेष अनुमति दी गई हो।

13.2. जैसा कि इस न्यायालय ने मल्लिकार्जुन कोडगली बनाम कर्नाटक राज्य, (2019) 2 एससीसी 752 में देखा, जहां तक पीड़ित का संबंध है, पीड़ित को अपील के लिए विशेष अनुमति प्रदान करने के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पीड़ित को धारा 372 प्रावधान के तहत अपील करने का वैधानिक अधिकार है और धारा 372 का प्रावधान शिकायतकर्ता के मामले में धारा 378 दं.प्र.सं की उपधारा (4) की तरह अपील के लिए विशेष अनुमति प्राप्त करने की कोई शर्त निर्धारित नहीं करता है और ऐसे मामले में जहां शिकायत पर स्थापित किसी भी मामले में बरी करने का आदेश पारित किया जाता है। पीड़ित को बरी करने के आदेश के खिलाफ अपील करने का अधिकार एक पूर्ण अधिकार है। इसलिए, जहां तक मुद्दा (ii) का संबंध है, अर्थात्, ऐसे मामले में जहां पीड़ित और/या शिकायतकर्ता, जैसा भी मामला हो, ने धारा 372 दं.प्र.सं या धारा 378(4) के तहत बरी किए जाने के आदेश के खिलाफ अपील पेश नहीं की है और/या उसका लाभ नहीं उठाया है, पीड़ित या शिकायतकर्ता, जैसा भी मामला हो, के अनुरोध पर बरी किए जाने के आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा और

पीड़ित या शिकायतकर्ता, जैसा भी मामला हो, को धारा 372 या धारा 378(4) के तहत प्रदत्त अपील पेश करने के लिए भेजा जाएगा। इसलिए मुद्दा (ii) का उत्तर तदनुसार दिया जाता है।"

(जोर दिया गया)

20. इसलिए, **जोसेफ स्टीफन केस** (उपरोक्त) और **मल्लिकार्जुन कोडागली केस** (उपरोक्त) के बाद, यह तय हो गया है कि धारा 372 दं.प्र.सं के प्रावधान के तहत अपील करने का पीड़ित का अधिकार पूर्ण है। पीड़ित को धारा 372 दं.प्र.सं के प्रावधान के तहत उच्च न्यायालय से अपील दायर करने के लिए कोई अनुमति या विशेष अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, शिकायत मामले में, शिकायतकर्ता, जो पीड़ित नहीं है, को उच्च न्यायालय से धारा 378(4) दं.प्र.सं के तहत आवश्यक विशेष अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता है ताकि वह उसके समक्ष अपील दायर कर सके। **जोसेफ स्टीफन केस** (उपरोक्त) के पैरा 13.1 की अंतिम पंक्ति से यह स्पष्ट है। इसके अलावा, शिकायत मामले और पुलिस मामले दोनों के पीड़ित समान रूप से धारा 372 दं.प्र.सं के प्रावधान के तहत उच्च न्यायालय में बिना किसी अनुमति या विशेष अनुमति के अपील दायर करने के हकदार हैं, जैसा कि धारा 378(3) और 378(4) दं.प्र.सं के तहत आवश्यक है, क्योंकि धारा 372 दं.प्र.सं का प्रावधान पुलिस मामले और शिकायत मामले के पीड़ित के बीच भेदभाव नहीं करता है।

21. याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वकील के प्रस्तुत करने में भी कोई सार नहीं है कि अपीलीय न्यायालय के फैसले के खिलाफ कोई आपराधिक अपील नहीं हो सकती है। यहाँ, यह इंगित करना प्रासंगिक हो जाता है कि आपराधिक अपील का उपचार क़ानून का सृजन है और जब तक कि यह दंड प्रक्रिया संहिता या उस समय लागू किसी अन्य कानून में प्रदान नहीं किया जाता है, तब तक कोई भी अपील बनाए रखने योग्य नहीं है जैसा कि धारा 372 दं.प्र.सं से स्पष्ट है और यह भी सच है कि धारा

393 दं.प्र.सं के अनुसार, आपराधिक अपीलों में पारित निर्णयों और आदेशों की आम तौर पर अंतिमता होती है।लेकिन यहां तक कि धारा 393 दं.प्र.सं धारा 377,378 और 384 दं.प्र.सं के प्रावधानों के अधीन धारा 393 दं.प्र.सं का सामान्य प्रावधान करके सामान्य नियम के कुछ अपवादों का प्रावधान करती है, जिसके तहत अपील निर्णयों के खिलाफ भी उच्च न्यायालय में अपील की गई है।यहां तक कि धारा 372 दं.प्र.सं के प्रावधान के तहत भी कोई शर्त नहीं है कि ऐसी अपील पीड़ितों द्वारा केवल निचली अदालत के फैसलों के खिलाफ दायर की जा सकती है।

22. अब, धारा 401 दं.प्र.सं की उपधारा (4) और (5) लागू होती है। धारा 401(4) दं.प्र.सं में प्रावधान है कि जहां आपराधिक अपील होती है और कोई अपील नहीं की जाती है, वहां अपील करने वाले पक्ष के कहने पर कोई आपराधिक पुनरीक्षण नहीं माना जा सकता। हालांकि, धारा 401(5) उच्च न्यायालय को आपराधिक पुनरीक्षण को आपराधिक अपील के रूप में मानने और उसके अनुसार उससे निपटने में सक्षम बनाती है।

23. धारा 401 दं.प्र.सं उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण शक्ति से संबंधित है जो निम्नानुसार हैः

> "**401. उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण की शक्तियाँ।-**(1) मामले में किसी ऐसी कार्यवाही का, जिसका अभिलेख स्वयं मंगाया गया है या जो अन्यथा उसके संज्ञान में आती है, उच्च न्यायालय अपने विवेकाधिकार पर, धारा 386,389,390 और 391 द्वारा अपील न्यायालय को या धारा 307 द्वारा सत्र न्यायालय को प्रदत्त किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है और जब पुनरीक्षण न्यायालय की रचना करने वाले न्यायाधीशों की राय समान रूप से विभाजित होती है, तो मामले का निपटारा धारा 392 द्वारा प्रदान की गई तरीके से किया जाएगा।

(2) इस धारा के तहत अभियुक्त या अन्य व्यक्ति के पूर्वाग्रह के लिए कोई आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसे व्यक्तिगत रूप से या अपने बचाव में वकील द्वारा सुने जाने का अवसर नहीं मिला हो।

(3) इस धारा की कोई भी बात उच्च न्यायालय को बरी किए जाने के निष्कर्ष को दोषसिद्धि में बदलने के लिए अधिकृत नहीं मानी जाएगी।

(4) जहाँ इस संहिता के तहत कोई अपील की जाती है और कोई अपील नहीं की जाती है, वहाँ उस पक्ष के कहने पर पुनरीक्षण के माध्यम से कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी जो अपील कर सकता था।

(5) जहां इस संहिता के तहत एक अपील निहित है, लेकिन किसी भी व्यक्ति द्वारा उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण के लिए एक आवेदन किया गया है और उच्च न्यायालय का समाधान हो जाता है कि ऐसा आवेदन इस गलत विश्वास के तहत किया गया था कि इसमें कोई अपील नहीं है और न्याय के हित में ऐसा करना आवश्यक है, उच्च न्यायालय पुनरीक्षण के लिए आवेदन को अपील की याचिका के रूप में मान सकता है और उसी के अनुसार व्यवहार कर सकता है।"

(जोर दिया गया)

24. यहां, जोसेफ स्टीफन मामले (उपरोक्त) का संदर्भ देना फिर से लाभदायक होगा, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संबंधित उच्च न्यायालय को निर्देश दिया है कि वह धारा 372 दं.प्र.सं के तहत आपराधिक पुनरीक्षण को आपराधिक अपील के रूप में माने और अपने स्वयं के गुण-दोष के आधार पर कानून के अनुसार इसका फैसला करे। हालांकि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक पुनरीक्षण को आपराधिक अपील के रूप में मानने के लिए, उच्च न्यायालय को आपराधिक पुनरीक्षण को आपराधिक अपील में बदलने के लिए न्यायिक आदेश पारित करना आवश्यक है। निर्णय का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:

> ".....जैसा कि उपरोक्त देखा गया है, पुनरीक्षण आवेदन को अपील की याचिका के रूप में मानने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 401 की उप-धारा (5) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय को एक न्यायिक आदेश पारित करने की आवश्यकता होती है।हालाँकि, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि अन्यथा पीड़ित होने के कारण भी उन्हें धारा 372 दं.प्र.सं. के प्रावधान के अनुसार अपील करने का वैधानिक अधिकार है, हम इस मामले को उच्च न्यायालय को भेजना उचित और उचित समझते हैं ताकि पुनरीक्षण आवेदनों को धारा 372 दं.प्र.सं. के तहत अपील की याचिका के रूप में माना जा सके और कानून के अनुसार और अपने गुण-दोष पर निर्णय लिया जा सके।यह सभी के हित में होगा, अर्थात् पीड़ितों के साथ-साथ अभियुक्त के भी, क्योंकि अपीलीय न्यायालय के पास पुनरीक्षण न्यायालय के बजाय एक अपीलीय न्यायालय के रूप में व्यापक दायरा और अधिकार क्षेत्र होगा।"
>
> (जोर दिया गया)

25. जोसेफ स्टीफन केस (उपरोक्त) पर भरोसा करते हुए, **झारखंड उच्च न्यायालय** ने **रेणु मिश्रा बनाम झारखंड राज्य और अन्य** (आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 520/2019, दिनांक 18.04.2024 को निर्णीत) के मामले में बरी किए जाने के अपीलीय निर्णय के विरुद्ध दायर आपराधिक पुनरीक्षण को गैर-धारणीय माना। परसुडीह थाना कांड संख्या 309/2012 से उत्पन्न इस मामले में, विद्वान ट्रायल कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी पाया था। हालांकि, दोषसिद्धि के निर्णय और सजा के आदेश को प्रथम अपीलीय न्यायालय ने खारिज कर दिया था। इसलिए, सूचक ने अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित बरी किए जाने के निर्णय के विरुद्ध झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष आपराधिक पुनरीक्षण को प्राथमिकता दी। उच्च न्यायालय ने **जोसेफ स्टीफन मामले** (उपरोक्त) के फैसले के आलोक में आपराधिक पुनरीक्षण को गैर-धारणीय मानते

हुए खारिज कर दिया और पीड़ित/याचिकाकर्ता को कानून के अनुसार उचित कदम उठाने की स्वतंत्रता दी।

वर्तमान मामला

26. मामले पर आते हुए, मैं पाता हूं कि पीड़ितों में से एक के फर्द बयान के आधार पर, जो यहाँ याचिकाकर्ता है, 2004 का परबत्ता पी. एस. मामला संख्या 258 फिर से आरोपी के खिलाफ दर्ज किया गया था जो यहाँ विपक्षी संख्या 2 है।मुकदमे के दौरान, उन्हें दोषी ठहराया गया था, लेकिन बाद में विपक्षी संख्या 2 द्वारा दायर आपराधिक अपील में, उन्हें बरी कर दिया गया था और पीड़ित/याचिकाकर्ता द्वारा बरी करने के अपीलीय फैसले के खिलाफ वर्तमान आपराधिक संशोधन दायर किया गया है।

27. उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों तथा बाध्यकारी न्यायिक उदाहरणों को देखते हुए, पीड़ित-याचिकाकर्ता के पास बिना किसी अनुमति या विशेष अनुमति के धारा 372 दं.प्र.सं के प्रावधान के तहत इस न्यायालय में आपराधिक अपील दायर करने का उपाय था। हालांकि, पीड़ित-याचिकाकर्ता ने वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण को प्राथमिकता दी है। लेकिन पीड़ित-याचिकाकर्ता के पास आपराधिक अपील के उपाय की उपलब्धता को देखते हुए, वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण धारा 401(4) दं.प्र.सं के अंतर्गत आता है। हालांकि, धारा 401 दं.प्र.सं की उप-धारा 5 इस न्यायालय को आपराधिक पुनरीक्षण को आपराधिक अपील में परिवर्तित करने और तदनुसार उसका विचार करने और गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेने में सक्षम बनाती है।

निष्कर्ष/आदेश

28. इसलिए, इस आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को आपराधिक अपील में परिवर्तित किया जाता है। कार्यालय को इस पुनरीक्षण याचिका में आवश्यक सुधार

करने और माननीय मुख्य न्यायाधीश की अनुमति से अपील को उचित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया जाता है।

(जितेंद्र कुमार, न्यायमूर्ति)

रविशंकर/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।